वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (घ) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा सहित देश के विभिन्न भागों से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋणों की मंजूरी, संवितरण और माफी और कथित अनियमितताओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उन्हें संबंधित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ उठाया जाता है। जहां तक अशोध्य ऋणों और घाटों को बट्टे खाते डालने और समझौता प्रस्तावों का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे ऐसे मामलों को जल्द निपटाने के लिए अपने विभिन्न अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित करें। बैंकों की जांच के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक की नजर में बैंकों में ऋण मूल्यांकन और अन्य मामलों से संबंधित व्याप्त विभिन्न कमियां भी आई हैं। निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार बैंकों द्वारा अपने दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।

गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंक

433 **श्री राम सिंह राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या सरकार इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में इन बैंकों की नई शाखाएं खोलने का विचार रखती हैं ;

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर इन शाखाओं को खोले जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या नीचे दी गयी :—

बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या		
	बडोदरा	सूरत	अहमदाबाद
भारतीय स्टेट बैंक . . .	32	9	14
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र . . .	—	—	1
बैंक आफ बड़ौदा	50	51	5
बैंक आफ इंडिया . . .	8	6	8
बैंक आफ महाराष्ट्र . . .	2	2	1
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया . . .	12	6	3
देना बैंक	10	21	23
इण्डियन बैंक . . .	1	1	—
इंडियन ओवरसीज बैंक . . .	6	1	5
सिंडिकेट बैंक	—	5	—
यूको बैंक	1	1	2
यूनियन बैंक आफ इंडिया . . .	8	4	4
विजया बैंक	1	—	—
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स . . .	—	—	1

(ख) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने की भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान नीति के अन्तर्गत, आवश्यक विवरण सहित प्रत्येक जिले में पता लगाए गए केन्द्रों की सूची उस जिले के लीड बैंक को दी जाती है । लीड बैंक, सभी बैंकों से प्राप्त सूचियों का समेकन करने के बाद उसे सिफारिश हेतु तथा सम्बन्धित राज्य सरकार के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजने के वास्ते जिला कलक्टर को प्रस्तुत करता है। शाखा लाइसेंसिंग नीति (1990–95) के अन्तर्गत, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का खोला जाना एक सतत प्रक्रिया है और इसलिए इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जाने वाली शाखाओं की संख्या का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

High level committee on tax restructure

434. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether a high level expert committee has been constituted to recommend measures to make the existing tax system more elastic broad-based and simple;

(b) if so, whether the Expert Committee has since submitted its report to Government; and

(c) if so, what are the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) The report has not become due yet.

Integration of tax laws under single code

435. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to integrate laws relating to income tax, wealth tax, and gift tax under a single national code for direct taxes;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) what is the extent to which the proposed scheme will be more effective and useful?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The three Direct Tax Laws, namely, Income-tax Act, Wealth-tax Act and Gift-tax Act, were conceived as parts of an integrated system of taxation. These are now proposed to be physically integrated by means of a Direct Taxes' Code. The Code will result in,—

(i) common procedural provisions,

(ii) rearrangement of the provisions of law on a more rational basis, and

(iii) deletion of provisions which are redundant under the present law.

Consequently, the Code is expected to make the administration of tax laws easy and convenient.

Schemes to MOP up black money

436. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Central Government propose to launch schemes for mopping up black money;